

कहानी: एक निर्णय जिसने करोड़ों किसानों की तकदीर बदल दी — डॉ. वर्गीज़ कुरियन (एक सच्ची घटना)

1949 में एक युवा इंजीनियर, **वर्गीज़ कुरियन**, सरकारी नौकरी की एक शर्त पूरी करने के लिए गुजरात के एक छोटे क़स्बे **आणंद** पहुँचे। वे वहाँ रुकना नहीं चाहते थे — अमेरिका से पढ़कर लौटे थे और बड़े शहर की चमक-दमक उन्हें बुला रही थी। पर आणंद में उन्होंने एक दृश्य देखा, जिसने उनका निर्णय बदल दिया।

खेड़ा ज़िले के छोटे दुग्ध-उत्पादक किसान, जिनमें बहुत-सी महिलाएँ थीं, अपना दूध बिचौलियों और एक निजी कंपनी को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर थे। किसान नेता **त्रिभुवनदास पटेल** ने 1946 में इन किसानों की एक सहकारी समिति बनाई थी, पर उसके पास न तकनीक थी, न प्रबंधन। त्रिभुवनदास ने कुरियन से कहा — "रुक जाओ, इन किसानों को तुम्हारी ज़रूरत है।" कुरियन के सामने दो रास्ते थे — अपना निजी करियर, या लाखों ग़रीब किसानों का भविष्य।

कुरियन रुक गए — और जीवन भर रुके रहे। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया, जिसमें **दक्षता और न्याय** दोनों साथ चले: आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण संयंत्र और ब्रांड (दक्षता — साधनभूत तार्किकता); और साथ ही यह सिद्धांत कि **दूध का मालिक किसान है**, उपभोक्ता के रुपये का बड़ा हिस्सा सीधे किसान तक पहुँचे, और हर गाँव की समिति लोकतांत्रिक ढंग से किसान ही चलाएँ (न्याय — मूल्य तार्किकता)। इसी से **"अमूल"** बना। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने **"ऑपरेशन फ़्लड"** शुरू किया, जिसने इस मॉडल को पूरे देश के गाँवों तक पहुँचाया।

आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध-उत्पादक देश है, और करोड़ों छोटे किसान, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और भूमिहीनों की है, इस व्यवस्था से रोज़ की आय पाते हैं। कुरियन के जन्मदिन **26 नवंबर** को भारत में **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** मनाया जाता है। उनका जीवन इस अध्याय का सार है — एक अच्छा निर्णय वह है, जो **सामाजिक न्याय** को केंद्र में रखे, **मानवीय संवेदना** से निकले, **जवाबदेह** संस्थाएँ बनाए, और **दक्षता तथा मूल्यों** — दोनों का संतुलन साधे।

इस कहानी से सीख: नैतिक निर्णय केवल "सही-ग़लत" का चुनाव नहीं, बल्कि दक्षता (साधनभूत तार्किकता) और न्याय (मूल्य तार्किकता) के संतुलन से ऐसी व्यवस्था बनाना है, जो सबसे कमज़ोर को सबसे अधिक लाभ दे। निजी करियर पर सार्वजनिक भलाई को चुनना ही लोकसेवा की आत्मा है।

शुरुआत एक सच्ची घटना से...

26 नवंबर 2008 की रात — मुंबई आतंकी हमले के दौरान, महाराष्ट्र आतंकवाद-विरोधी दस्ते (ATS) के प्रमुख हेमंत करकरे अपर्याप्त सुरक्षा वाली पुरानी बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहनकर ही मोर्चे पर निकल पड़े — फिर भी वे पीछे नहीं हटे और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। उनका यह निर्णय किसी एक दार्शनिक सिद्धांत से नहीं, बल्कि कई नैतिक धाराओं के संगम से उपजा था — गीता का 'लोकसंग्रह' (समाज-कल्याण की भावना), कांट का 'कर्तव्य के लिए कर्तव्य', और प्लेटो का 'साहस' नामक सद्रूप — सब एक साथ उस निर्णय में समाया हुआ था। असल सवाल यही है — कोई निर्णय आखिर 'नैतिक' कब कहलाता है, और एक जटिल परिस्थिति में सही निर्णय तक पहुँचने की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया भी होती है क्या? यही इस अध्याय का केंद्रीय विषय है — सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदनशीलता, जवाबदेही और तार्किकता (Rationality) के ठोस आधारों पर खड़ा एक नैतिक निर्णय-ढाँचा।

अध्याय 08 — एक नज़र में

चित्र 8.1: अध्याय 08 — एक नज़र में

कहानी: अध्याय की यात्रा — "जनसुनवाई का एक दिन: उपखंड अधिकारी मीरा"

(यह एक काल्पनिक कहानी है। जनसुनवाई के हर मामले में इस अध्याय का एक भाग छिपा है।)

हर गुरुवार की तरह उपखंड अधिकारी मीरा की जनसुनवाई में सुबह से भीड़ थी। उनकी मेज़ पर एक छोटी पट्टिका रखी थी, जिस पर उनके प्रशिक्षक की एक पंक्ति लिखी थी — "हर फ़ाइल के पीछे एक चेहरा है।"

पहला मामला — कौन-सा निर्णय नैतिक? दो पड़ोसी गाँवों के बीच चरागाह का विवाद था। मीरा ने सोचा — नियम क्या कहता है (कर्तव्य), अधिक लोगों का भला किसमें है (परिणाम), और एक न्यायप्रिय व्यक्ति क्या करता (सद्गुण)? (खंड 1 और 2)

दूसरा मामला — सामाजिक न्याय: एक भील बालिका की माँ आई — बेटी ने दसवीं में अच्छे अंक पाए, पर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाया, क्योंकि गाँव में इंटरनेट ही नहीं था। मीरा को समझ आया कि समान नियम, असमान परिस्थितियों में अन्याय भी बन सकता है। (खंड 3)

तीसरा मामला — मानवीय चिंता: बाढ़-राहत शिविर से ख़बर आई कि कुछ प्रवासी मज़दूर परिवारों को पहचान-पत्र न होने के कारण राशन नहीं मिल रहा। मीरा ने तुरंत आदेश दिया — "भूख पहचान-पत्र नहीं देखती।" (खंड 4)

चौथा मामला — जवाबदेही: एक नई सड़क छह महीने में ही उखड़ गई थी। लोग नाराज़ थे। मीरा ने तय किया — जाँच होगी, ज़िम्मेदारी तय होगी, ठेकेदार से मरम्मत करवाई जाएगी, और रिपोर्ट सबके सामने रखी जाएगी। (खंड 5)

पाँचवाँ मामला — निर्णय की कसौटी: एक उद्योग को नियमों में ढील देने का प्रस्ताव आया। मीरा ने अपने निर्णय को परखा — क्या मैं इसे अख़बार में छपने दे सकती हूँ? अगर मैं प्रभावित ग्रामीण होती, तो क्या इसे स्वीकार करती? (खंड 6)

छठा मामला — मन, संस्था और समाज: मीरा ने देखा कि उनके दफ़्तर का माहौल, उनके वरिष्ठों का रवैया और समाज की अपेक्षाएँ — सब उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। (खंड 7)

शाम — दक्षता और मूल्य: दिन के अंत में डैशबोर्ड पर लिखा था — "आज 112 शिकायतें निपटाई गईं।" मीरा मुस्कुराई — गिनती दक्षता बताती है, पर कितने लोगों को सचमुच न्याय मिला, यह मूल्य बताते हैं। आदर्श प्रशासन दोनों से बनता है। (खंड 8 से 10)

इस कहानी से सीख: यह अध्याय नैतिक निर्णय के दार्शनिक आधारों से शुरू होकर सामाजिक न्याय, मानवीय चिंताओं, जवाबदेही, निर्णय की प्रक्रिया और परीक्षणों, निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों तथा साधनभूत और मूल्य तार्किकता के संतुलन तक जाता है।

मीरा की जनसुनवाई — अध्याय के सात पड़ाव



चित्र 8.2: मीरा की जनसुनवाई — अध्याय के सात पड़ाव

अध्याय विषय-सूची

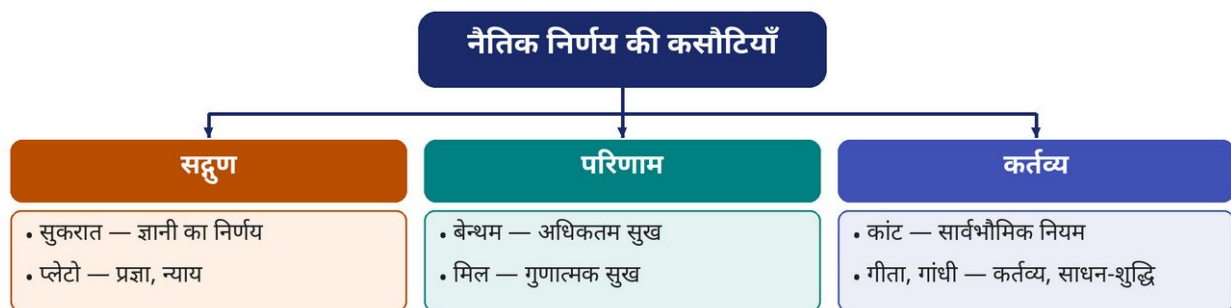
1 कौन-सा निर्णय नैतिक कहलाता है? — 7 दार्शनिक दृष्टिकोण	6 नैतिक निर्णय की 5-चरण प्रक्रिया एवं 10 परीक्षण
2 नैतिक निर्णय लेने के 14 आधार (Basis of Ethical Decision Making)	7 नैतिक निर्णय में योगदान करने वाले कारक
3 सामाजिक न्याय (Social Justice)	8 साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता (Instrumental vs Value Rationality)
4 मानवीय चिंताएँ (Humanitarian Concerns)	9 आगे की राह — संतुलित दृष्टिकोण (Way Forward)
5 शासन में जवाबदेही (Accountability in Governance)	10 नैतिक निर्णय-निर्माण — ऐतिहासिक यात्रा

1. कौन-सा निर्णय नैतिक कहलाता है? — 7 दार्शनिक दृष्टिकोण

अलग-अलग दार्शनिक परंपराओं ने 'नैतिक निर्णय' को अलग-अलग कसौटियों से परखा है। नीचे दी गई तालिका इन सातों दृष्टिकोणों को सरल भाषा व प्रशासनिक उदाहरणों सहित प्रस्तुत करती है — ध्यान दें कि ये सभी दृष्टिकोण अध्याय 6 में विस्तार से पढ़े जा चुके सिद्धांतों (सुकरात, प्लेटो, बेन्थम, मिल, कांट आदि) का ही एक संक्षिप्त, निर्णय-केंद्रित पुनरावलोकन हैं।

दार्शनिक/स्रोत	नैतिक निर्णय की कसौटी	प्रशासनिक उदाहरण
सुकरात (Socrates)	वह निर्णय नैतिक है, जो ज्ञानी व्यक्ति द्वारा लिया जाए — "ज्ञान ही सद्गुण है, अज्ञानता पाप है।"	आचार-संहिता व कानूनों का पूर्ण ज्ञान होने पर ही बेहतर निर्णय संभव।
भगवद्गीता	जो निर्णय लोकसंग्रह (सामाजिक कल्याण) व निष्काम कर्म (बिना फल की इच्छा) की भावना से लिया जाए।	26/11 मुंबई हमले में ATS प्रमुख हेमंत करकरे का बलिदान — कर्तव्य सर्वोपरि।
प्लेटो (Plato)	जो निर्णय चार सद्गुणों — प्रज्ञा, साहस, संयम व न्याय — पर आधारित हो।	IAS दुर्गा शक्ति नागपाल — रेत-खनन माफ़िया के विरुद्ध साहसिक कार्रवाई (साहस)।
जेरेमी बेन्थम	अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख — मात्रात्मक उपयोगितावाद।	सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) — सर्वाधिक लोगों को लाभ।
जॉन स्टुअर्ट मिल	गुणात्मक उपयोगितावाद — उच्च बौद्धिक/नैतिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ मानना।	लक्षित बुनियादी आय (Targeted Basic Income) — जीवन-गुणवत्ता पर बल।
हिंदू दर्शन	जो निर्णय धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष — इन चार पुरुषार्थों का पालन करे।	लोक-सेवा = धर्म; संसाधनों का उपयोग = अर्थ।
गांधीजी (जंतर — Talisman)	जो निर्णय सबसे गरीब व कमज़ोर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो।	अंत्योदय — समाज के अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता।

सात दृष्टिकोण — तीन स्तंभों में



चित्र 8.3: सात दृष्टिकोण — तीन स्तंभों में

ये 7 दृष्टिकोण अध्याय 6 के तीन-स्तंभ वर्गीकरण से सीधे जुड़े हैं — सुकरात और प्लेटो **सद्गुण-नीतिशास्त्र** में, बेन्थम और मिल **परिणामवाद** में, और कांट जैसा **कर्तव्यवाद** गीता और गांधी के दृष्टिकोण में झलकता है। सरल शब्दों में — सद्गुण-नीतिशास्त्र पूछता है कि 'एक अच्छा और चरित्रवान व्यक्ति इस स्थिति में क्या करता?', परिणामवाद पूछता है कि 'किस निर्णय से सबसे अधिक लोगों का भला होगा?', और कर्तव्यवाद पूछता है कि 'मेरा कर्तव्य क्या है, परिणाम चाहे जो हो?' हिंदू दर्शन का पुरुषार्थ-विचार जीवन के इन सभी पक्षों में संतुलन की बात करता है।

2. नैतिक निर्णय लेने के 14 आधार (Basis of Ethical Decision Making)

एक नैतिक प्रशासनिक निर्णय सामान्यतः 14 आधार-स्तंभों में से कई पर एक साथ टिका होता है — नीचे इन्हें क्रमबद्ध रूप से सरल व्याख्या सहित दिया गया है।

क्र.	आधार	सरल व्याख्या
1	ईमानदारी व सत्यनिष्ठा (Honesty & Integrity)	निर्णय लेने वाले का चरित्र निष्कलंक हो — व्यक्तिगत लाभ की सोच न हो।
2	विश्वास व वफ़ादारी (Trust & Loyalty)	संविधान व लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अटूट निष्ठा।
3	निष्पक्षता व न्याय (Fairness & Justice)	शक्ति का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए — किसी के प्रति पक्षपात नहीं।
4	मानवाधिकार व गरिमा की चिंता	हर मनुष्य की गरिमा का सम्मान — देखभाल, करुणा व दयालुता।
5	मानवीय चिंताएँ (Humanitarian Concerns)	मानवता के बड़े संकटों के प्रति संवेदनशीलता।
6	कानून, नियम व विनियम	निर्णय संवैधानिक व वैधानिक ढाँचे के अनुरूप हो।
7	उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता (Excellence)	सर्वोत्तम परिणाम के लिए सतत प्रयासरत रहना।
8	जवाबदेही (Accountability)	निर्णयों के परिणामों की ज़िम्मेदारी स्वयं लेना।
9	स्पष्ट अंतरात्मा (Clear Conscience)	अंतरात्मा की आवाज़ को आंतरिक नैतिक कम्पास मानना।
10	सामाजिक मानदंड व संस्कृति	समाज की मान्यताओं व परंपराओं का सम्मान।
11	परिणामों की चिंता (Consequences)	निर्णय के दीर्घकालिक व अल्पकालिक प्रभावों का आकलन।
12	सामाजिक न्याय (Social Justice)	वंचित व हाशियाकृत वर्गों हेतु संसाधनों का उचित वितरण।

क्र.	आधार	सरल व्याख्या
13	मानवता व करुणा (Humanity)	ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति व सक्रिय सहायता।
14	विवेकाधिकार का उचित उपयोग	विशेष परिस्थितियों में नियमों से परे जाकर मानवीय निर्णय लेना।

नैतिक निर्णय के 14 आधार — चार समूह

चरित्र ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, साहस	न्याय और मानवता निष्पक्षता, करुणा, सामाजिक न्याय	संस्थागत-वैधानिक कानून, नियम, जवाबदेही, पारदर्शिता	संदर्भ और लचीलापन परिस्थिति, विवेक, दीर्घकालिक दृष्टि
---	--	--	---

चित्र 8.4: नैतिक निर्णय के 14 आधार — चार समूह

इन 14 आधारों को चार समूहों में समझना आसान है — (1) **चरित्र** से जुड़े (1, 2, 9), (2) **न्याय और मानवता** से जुड़े (3, 4, 5, 12, 13), (3) **संस्थागत/वैधानिक** (6, 7, 8), (4) **संदर्भ और लचीलापन** (10, 11, 14)। किसी भी वास्तविक निर्णय में इनमें से 4-5 आधार सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं।

3. सामाजिक न्याय (Social Justice)

☀️ प्रामाणिक कथन

"कहीं भी अन्याय, हर जगह न्याय के लिए खतरा है" (Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.) — मार्टिन लूथर किंग जूनियर

🔍 आसान परिभाषा: सामाजिक न्याय एवं ROPE सूत्र

📖 **परिभाषा:** सामाजिक न्याय का अर्थ है — समाज में संसाधनों, अवसरों व विशेषाधिकारों का उचित वितरण, तथा सभी वर्गों (विशेषकर वंचित व हाशियाकृत) का सशक्तिकरण। इसे सरलता से 'ROPE' सूत्र द्वारा याद किया जा सकता है।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक परिवार में माता-पिता अपने सभी बच्चों को समान संसाधन (भोजन, शिक्षा) व अवसर देने की कोशिश करते हैं, भले ही किसी बच्चे को अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत हो — राज्य भी अपने सभी नागरिकों के लिए ठीक ऐसी ही भूमिका निभाता है। 🏠
उदाहरण: R = संसाधन (Resources) का न्यायपूर्ण वितरण, O = समान अवसर (Opportunities), P = विशेषाधिकारों में समानता (Privileges), E = सभी का सशक्तिकरण (Empowerment)। सामाजिक न्याय हेतु प्रतिवर्ष 20 फ़रवरी को 'विश्व सामाजिक न्याय दिवस' (UN World Day of Social Justice) मनाया जाता है। रोज़मर्रा में इसे ऐसे समझें — हर गाँव में स्कूल और अस्पताल पहुँचाना संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है; नौकरी की भर्ती में हर उम्मीदवार को एक-सा मौक़ा मिलना समान अवसर है; जन्म, जाति या पैसे के आधार पर किसी को विशेष छूट न मिलना विशेषाधिकारों में समानता है; और महिलाओं व वंचितों को इतना सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें, सशक्तिकरण है।

ROPE सूत्र — सामाजिक न्याय के चार स्तंभ

सामाजिक न्याय

R — संसाधन न्यायपूर्ण वितरण	O — अवसर सबको समान अवसर	P — विशेषाधिकार जन्म-आधारित विशेषाधिकार का अंत	E — सशक्तिकरण वंचितों की आवाज़ और क्षमता
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--

चित्र 8.5: ROPE सूत्र — सामाजिक न्याय के चार स्तंभ

समानता बनाम समता — सामाजिक न्याय की कुंजी

समानता (Equality)	बनाम	समता (Equity)
सबको एक जैसा देना	अर्थ	ज़रूरत के अनुसार देना
सबकी शुरुआत एक-सी है	मान्यता	शुरुआत असमान है
सबके लिए एक ही ऑनलाइन फ़ॉर्म	उदाहरण	इंटरनेट-रहित गाँवों के लिए विशेष शिविर
अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समता	संविधान	अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46 — विशेष प्रावधान

चित्र 8.6: समानता बनाम समता — सामाजिक न्याय की कुंजी

3.1 सामाजिक न्याय क्यों ज़रूरी है? — 8 कारण

क्र.	कारण	दार्शनिक/संदर्भ
1	शांतिपूर्ण व समृद्ध समाज के लिए	असमानता से क्रांतियाँ जन्म लेती हैं (जैसे फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति)।
2	मानव-गरिमा व विविधता का उत्सव	इमैनुएल कांट — मनुष्य साध्य है, साधन नहीं।
3	संसाधनों का कुशल उपयोग	गांधीजी — पृथ्वी सबकी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लालच नहीं।
4	सुख की अधिकतमता	अरस्तू का 'समम् बोनम' (Summum Bonum) — सर्वोच्च शुभ या कल्याण (Highest Good), यानी ऐसा अच्छा जीवन जिसे पाने के लिए बाक़ी सब किया जाता है।
5	जॉन रॉल्स का न्याय-सिद्धांत	अज्ञानता का आवरण (Veil of Ignorance) — पक्षपात-रहित निर्णय।
6	राज्य का संवैधानिक कर्तव्य	अनुच्छेद 38 (सामाजिक-आर्थिक न्याय) व अनुच्छेद 39 (संसाधन-वितरण) — राज्य के नीति-निदेशक तत्व, संविधान में 1949-50 से निहित।
7	लोकसंग्रह व सर्वोदय	गीता का 'लोकसंग्रह' + गांधीजी का सर्वोदय-अंत्योदय।
8	गांधीजी का जंतर (Talisman)	निर्णय की कसौटी — समाज के अंतिम व्यक्ति पर प्रभाव।

3.2 सामाजिक न्याय के उदाहरण

क्षेत्र	उदाहरण
अंतरराष्ट्रीय	अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन (1950-60 का दशक) — मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 — समानता व अस्पृश्यता-उन्मूलन।
सकारात्मक भेदभाव	आरक्षण की माँग, दलित आंदोलन (1970 का दशक), LGBTQ+ अधिकार।
जन-आंदोलन	अन्ना हज़ारे — भ्रष्टाचार के विरुद्ध; नियमगिरि सुरक्षा समिति (ओडिशा) — आदिवासी अधिकार।
सरकारी योजनाएँ	मनरेगा, PM आवास योजना, PM किसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
दृष्टिकोण-परिवर्तन	'विकलांग' से 'दिव्यांगजन' — भाषा में गरिमा; तृतीय-लिंग की मान्यता।

संविधान में सामाजिक न्याय: संविधान की प्रस्तावना **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** का वचन देती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में **अनुच्छेद 38** राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता घटे; **अनुच्छेद 39(ग)** यह सुनिश्चित करने को कहता है कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी न हो, जिससे धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में अहितकारी केंद्रीकरण हो; और **अनुच्छेद 46** कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल का निर्देश देता है।

सुशासन में सामाजिक न्याय और समता: सुशासन का अर्थ है — शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में **समान अवसर** देकर सामाजिक-आर्थिक असमानता घटाना; **कल्याणकारी योजनाओं** को प्रभावी ढंग से लागू करके उनका लाभ वंचित और हाशिये के वर्गों तक पहुँचाना; अभिव्यक्ति, सभा और विधि के समक्ष समता जैसे **मानवाधिकारों की रक्षा**; और **अल्पसंख्यकों के अधिकारों** की रक्षा कर उन्हें सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में शामिल करना। आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है — इसीलिए गांधी ने अमीर-गरीब की खाई पाटने को राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य माना, और आंबेडकर ने सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की पूर्व-शर्त।

सामाजिक न्याय के दार्शनिक आधार: जॉन रॉल्स का अंतर-सिद्धांत (असमानता तभी स्वीकार्य, जब वह सबसे वंचित के हित में हो), **अमर्त्य सेन** का क्षमता उपागम (केवल संसाधन नहीं, बल्कि उन्हें उपयोग करने की वास्तविक क्षमता), और **अरस्तू** का वितरणात्मक न्याय (समान मामलों में समान, असमान में असमान व्यवहार) — तीनों मिलकर बताते हैं कि सामाजिक न्याय "सबको एक-सा" देना नहीं, बल्कि "हर किसी को आगे बढ़ने का वास्तविक अवसर" देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में **20 फरवरी** को **विश्व सामाजिक न्याय दिवस** घोषित किया, जो 2009 से मनाया जाता है।

3.3 प्रशासन में सामाजिक न्याय की भूमिका

- ◆ कल्याणकारी योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना (Last Mile Delivery) — यानी योजना केवल कागज़ पर या ज़िला मुख्यालय तक सीमित न रहे, बल्कि दूर-दराज़ के गाँव में बैठे सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसका लाभ सचमुच मिले।
- ◆ प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation) — अधिक आय वालों पर अधिक कर, गरीबों को राहत।
- ◆ आरक्षण व सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) — जिन वर्गों को सदियों तक शिक्षा, नौकरी और सम्मान के अवसर नहीं मिले, उन्हें विशेष अवसर देकर बाक़ी समाज की बराबरी पर लाना।
- ◆ राजस्थान के उदाहरण — इंदिरा रसोई योजना (अब श्री अन्नपूर्णा रसोई), जिसमें ज़रूरतमंदों को बहुत कम दाम पर पौष्टिक भोजन मिलता है; कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसमें अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है ताकि दूरी के कारण उनकी पढ़ाई न छूटे; और पालनहार योजना, जिसमें अनाथ व बेसहारा बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है।

कहानी: "छात्रवृत्ति का पोर्टल और इंटरनेट-रहित गाँव" — समान नियम, असमान परिस्थिति

उदयपुर ज़िले के कोटड़ा क्षेत्र में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी **प्रकाश** (काल्पनिक नाम) ने देखा कि इस वर्ष मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति के आवेदन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधे रह गए थे। कारण जल्दी समझ आ गया — इस बार आवेदन केवल **ऑनलाइन पोर्टल** से हो रहे थे। शहर के छात्रों के लिए यह सुविधा थी, पर दूर के आदिवासी गाँवों में न इंटरनेट था, न ई-मित्र केंद्र, और कई परिवारों के पास बैंक खाते का आधार से जुड़ाव भी नहीं था।

नियम सबके लिए एक-सा था — अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा — "जिसे ज़रूरत है, वह आवेदन करेगा; हम हर बच्चे के घर नहीं जा सकते।" प्रकाश ने सोचा — क्या "सबके लिए एक-सा नियम" उस बच्ची के लिए भी न्यायपूर्ण है, जिसे आवेदन के लिए तीस किलोमीटर दूर जाना पड़े? समानता यहाँ अन्याय बन रही थी; ज़रूरत **समता** की थी।

प्रकाश ने अंतिम तिथि से तीन हफ्ते पहले "**छात्रवृत्ति सप्ताह**" चलाया — हर पंचायत मुख्यालय पर विद्यालयों के साथ मिलकर विशेष शिविर, जहाँ लैपटॉप और मोबाइल इंटरनेट के साथ कर्मचारी बैठे; बैंक प्रतिनिधियों ने वहीं खातों को आधार से जोड़ा; और जनजातीय छात्रावासों के अधीक्षकों को हर पात्र छात्र की सूची बनाकर आवेदन करवाने की ज़िम्मेदारी दी गई। जो दस्तावेज़ तुरंत उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए राज्य-स्तर से अनुमति लेकर बाद में जमा करने की छूट दिलवाई।

अंतिम तिथि तक आवेदन पिछले वर्ष से भी 18% अधिक हो गए, और उनमें लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक बढ़ा। अगले वर्ष राज्य ने यह मॉडल सभी जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में लागू किया। प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा — "डिजिटल व्यवस्था दक्षता लाती है, पर अगर उसका दरवाज़ा सबसे कमज़ोर तक न पहुँचे, तो वह नई असमानता बन जाती है।"

 **इस कहानी से सीख:** सामाजिक न्याय का अर्थ समान नियम नहीं, बल्कि समान अवसर है। जब परिस्थितियाँ असमान हों, तो समता (ज़रूरत के अनुसार विशेष व्यवस्था) ही न्याय है। "डिजिटल विभाजन" जैसी नई असमानताओं के प्रति सजगता आज के प्रशासक का अनिवार्य गुण है।

समानता और समता का अंतर: समानता (Equality) का अर्थ है सबको एक जैसा देना, जबकि सामाजिक न्याय की भावना **ज़रूरत के अनुसार अतिरिक्त सहयोग** — यानी समता (Equity) — में निहित है, जैसा आरक्षण नीति में दिखता है। ROPE सूत्र इसी समता को व्यवहार में उतारता है।

4. मानवीय चिंताएँ (Humanitarian Concerns)

मानवीय चिंता वह घटना या परिस्थिति है जो बड़े पैमाने पर मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करती है — प्राकृतिक हो या मानव-निर्मित। एक संवेदनशील प्रशासक को इन चिंताओं के प्रति सदैव सजग व सक्रिय रहना चाहिए।

मानवीय चिंता	घटनाएँ / अभियान (Operations)	प्रशासनिक भूमिका व उदाहरण
1. प्राकृतिक आपदाएँ (Natural Disasters)	नेपाल भूकंप 2015 → 'ऑपरेशन मैत्री'; केरल बाढ़ 2018; सुनामी 2004; तुर्की-सीरिया भूकंप 2023 → 'ऑपरेशन दोस्त'।	IAS कन्नन गोपीनाथन — केरल बाढ़ में 8 दिन घर नहीं गए; MG राजामणिक्यम — स्वयं कंधे पर चावल की बोरी उठाई।
2. महामारी (Epidemics/Pandemics)	कोविड-19 (2020-21)।	भीलवाड़ा मॉडल — IAS राजेंद्र भट्ट व टीना डाबी; 'वैक्सीन मैत्री' पहल — लगभग 100 देशों को वैक्सीन आपूर्ति।
3. सीमापार संकट (Cross-border Crisis)	यूक्रेन युद्ध 2022 → 'ऑपरेशन गंगा'; सूडान संकट 2023 → 'ऑपरेशन कावेरी'।	भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी व स्वदेश-वापसी — कूटनीतिक व प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण।
4. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)	पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance), PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।	भारत की जलवायु-नीति सौर व जैव-ईंधन (Biofuel) नीतियों पर केंद्रित — जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index) में भारत की रैंकिंग वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है।

मानवीय चिंता	घटनाएँ / अभियान (Operations)	प्रशासनिक भूमिका व उदाहरण
5. आतंकवाद (Terrorism)	26/11 मुंबई हमला; संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना बल (UN Peacekeeping Forces)।	भारत — संयुक्त राष्ट्र में सैनिक-योगदान देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक।
6. गरीबी (Poverty)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), मनरेगा, PM किसान, उज्ज्वला योजना।	खाद्य + आजीविका + ऊर्जा सुरक्षा — बहु-आयामी (Multi-dimensional) दृष्टिकोण।
7. शरणार्थी संकट (Refugee Crisis)	नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) — प्रताड़ित अल्पसंख्यकों हेतु; तिब्बती शरणार्थी (1950 का दशक); रोहिंग्या (म्यांमार)।	भारत एक 'करुणाशील मेज़बान' (Compassionate Host) की भूमिका में — मानवीय आधार पर शरण।

4.1 मानवीय कार्रवाई के चार सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवीय सहायता के लिए चार मूल सिद्धांत स्वीकार किए हैं — **मानवता** (जहाँ भी मानवीय पीड़ा हो, उसे दूर करना; जीवन और गरिमा की रक्षा), **तटस्थता** (किसी संघर्ष में किसी पक्ष का साथ न देना), **निष्पक्षता** (सहायता केवल ज़रूरत के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के — सबसे ज़रूरतमंद को प्राथमिकता) और **स्वतंत्रता** (मानवीय उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य उद्देश्यों से स्वतंत्र रहें)। एक ज़िला प्रशासक के लिए भी आपदा-राहत में यही चार सिद्धांत मार्गदर्शक हैं।

मानवीय कार्रवाई के चार सिद्धांत

मानवीय सहायता

मानवता पीड़ा दूर करना, गरिमा की रक्षा	तटस्थता किसी पक्ष का साथ नहीं	निष्पक्षता केवल ज़रूरत के आधार पर	स्वतंत्रता राजनीतिक उद्देश्यों से मुक्त
---	---	---	---

चित्र 8.7: मानवीय कार्रवाई के चार सिद्धांत

अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून (जिनेवा अभिसमय, 1949) के मूल नियम: (1) जो लोग युद्ध में भाग नहीं ले रहे या युद्ध से बाहर हो चुके हैं, उनके जीवन और शारीरिक-नैतिक अखंडता का सम्मान हो और उनसे हर हाल में मानवीय व्यवहार हो; (2) आत्मसमर्पण करने वाले या युद्ध से बाहर हो चुके शत्रु को मारना या घायल करना निषिद्ध है; (3) घायलों और बीमारों की देखभाल हो, और चिकित्सा-कर्मियों, अस्पतालों तथा रेड क्रॉस/रेड क्रिसेंट चिह्न का सम्मान हो; (4) बंदी सैनिकों और नागरिकों के जीवन, गरिमा और विश्वासों का सम्मान हो, उन्हें परिवार से संपर्क का अधिकार हो; (5) किसी पर यातना, शारीरिक दंड या अपमानजनक व्यवहार न हो; (6) अनावश्यक पीड़ा देने वाले हथियार और तरीक़े निषिद्ध हैं; (7) नागरिकों और लड़ाकों में हमेशा भेद हो — हमले केवल सैन्य लक्ष्यों पर हों।

सैन्य/सुरक्षा बलों के लिए नैतिक मार्ग: यदि वरिष्ठ कोई अनैतिक आदेश दें, तो विकल्प हैं — त्यागपत्र, आदेश के पालन से इनकार, विरोध-स्वरूप तबादले का अनुरोध, या आदेश देने वाले से ऊँचे अधिकारी के हस्तक्षेप की माँग। 'युद्ध के बाद का न्याय' (Jus post bellum) का सिद्धांत कहता है कि युद्ध समाप्त होने पर होने वाले शांति-समझौते सभी पक्षों के लिए न्यायसंगत हों — विजेता केवल बदला न ले, बल्कि पुनर्निर्माण और न्याय की व्यवस्था करे — और दीर्घकालिक शांति की परिस्थितियाँ बनाएँ।

4.2 मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण की नैतिकता

सहायता क्यों? — दार्शनिक कारण: (1) हमने राष्ट्र-राज्यों की कृत्रिम सीमाएँ खींची हैं, पर हम सब एक ही मानव-जाति हैं; (2) ऐतिहासिक बोझ — कई पूर्व औपनिवेशिक देशों ने अन्य देशों के शोषण से विकास किया, इसलिए क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता उनका दायित्व है; (3) **त्याग का सिद्धांत** — संपन्न का कर्तव्य है कि वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग उनकी रक्षा के लिए त्यागे, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते।

सहायता का प्रकार	अर्थ / उदाहरण
मानवीय सहायता	आपात स्थिति में और उसके बाद जीवन बचाने, पीड़ा कम करने और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए — जैसे ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन दोस्त
तकनीकी सहायता	उपकरण नहीं, तकनीकी ज्ञान और क्षमता-निर्माण — सबसे कम खर्चीली, अधिक लाभकारी; जैसे भारत की पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना
आर्थिक सहायता	बहुत कम ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण, बुनियादी ढाँचे के लिए
द्विपक्षीय / बहुपक्षीय	भारत द्वारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका को सहायता / विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ब्रिक्स बैंक द्वारा
परियोजना सहायता	अफ़ग़ानिस्तान में भारत द्वारा सलमा बाँध (भारत-अफ़ग़ान मैत्री बाँध)
स्वैच्छिक सहायता	सीमाओं से परे काम करने वाली डॉक्टरों की स्वयंसेवी संस्थाएँ, जैसे 'डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (Médecins Sans Frontières)
सैन्य सहायता	सबसे विवादित — पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है

अंतरराष्ट्रीय सहायता के नैतिक मुद्दे: (1) राज्य बनाम गैर-राज्य माध्यम — अगर सहायता सीधे प्राप्तकर्ता देश की सरकार को दी जाए, तो कई बार वह अक्षमता या लालफीताशाही में व्यर्थ खर्च हो जाती है; और अगर सरकार को दरकिनार करके सीधे गैर-सरकारी संस्थाओं को दी जाए, तो उस देश की संप्रभुता (अपने मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार) पर प्रश्न उठता है; **(2) शर्तें** — सहायता के साथ ऐसी शर्तें, जो प्राप्तकर्ता की सबसे ज़रूरी प्राथमिकताओं के बजाय दाता की प्राथमिकताएँ थोपें — इसे कई लोग "दूसरे तरीकों से उपनिवेशवाद" कहते हैं; **(3) एकल-संस्कृतिवाद** — दाता देश सहायता के साथ अपनी संस्कृति, जीवन-शैली और काम करने के तौर-तरीके थोप देता है, जिससे स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं की उपेक्षा होती है; **(4) पुरानी तकनीक का हस्तांतरण** — विकसित देशों की पुरानी, अनुपयोगी हो चुकी तकनीक सहायता के नाम पर दे देना; ; **(5) भ्रष्टाचार** — कई संकटों में सहायता का बहुत छोटा हिस्सा ही प्रभावितों तक पहुँचता है; **(6) निर्भरता** — राज्य अपनी नीतियों के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर होने लगता है; **(7) विद्रोही समूहों को अप्रत्यक्ष लाभ** — परिवहन, आयात या गोदामों पर "कर" वसूलकर; और **(8) वित्तीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक घाटा** — मतदान-शक्ति कुछ विकसित देशों के पक्ष में।

☀ राजस्थान-विशेष उदाहरण — भीलवाड़ा मॉडल

कोविड-19 की पहली लहर (मार्च 2020) में जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने भीलवाड़ा जिले की सीमाओं को पूर्णतः सील (Seal) किया, तथा तत्कालीन उपखंड अधिकारी (SDM) टीना डाबी ने आगे कार्यान्वयन सुनिश्चित किया — यह मॉडल पूरे देश में प्रशंसित हुआ। यह मानवीय संवेदनशीलता (प्रवासी मज़दूरों की सहायता) व जवाबदेही — दोनों का उत्कृष्ट संगम है।

📖 कहानी: "भूख पहचान-पत्र नहीं देखती" — बाढ़-राहत शिविर की दुविधा

बारां ज़िले में अचानक आई बाढ़ के बाद एक राहत शिविर में लगभग 800 लोग थे। तीसरे दिन तहसीलदार राजेश (काल्पनिक नाम) को शिकायत मिली कि शिविर में रह रहे लगभग 60 प्रवासी मज़दूर परिवारों — जो पास के ईंट-भट्टों पर काम करते थे और दूसरे राज्य से आए थे — को सूखा राशन नहीं दिया जा रहा। राशन-वितरण करने वाले कर्मचारी का तर्क था — "नियम के अनुसार राहत-सामग्री केवल उन्हें मिलेगी, जिनका नाम प्रभावित परिवारों की सूची में है और जिनके पास स्थानीय पहचान-पत्र है।"

राजेश के सामने दुविधा थी — एक ओर लेखा-परीक्षा (ऑडिट) का डर, कि बिना पहचान के बाँटी गई सामग्री का हिसाब कैसे देंगे; दूसरी ओर भूखे बच्चे, जिनका एक ही "अपराध" था कि वे किसी और राज्य में पैदा हुए थे। उन्हें मानवीय सहायता का सिद्धांत याद आया — **निष्पक्षता: सहायता केवल ज़रूरत के आधार पर, बिना भेदभाव।**

राजेश ने तत्काल लिखित आदेश दिया — शिविर में रह रहे हर व्यक्ति को, पहचान-पत्र हो या न हो, भोजन और राशन मिलेगा। लेखा-जोखा के लिए हर प्रवासी परिवार का फ़ोटो सहित एक सरल पंजीकरण किया गया, ईंट-भट्टा मालिकों से उनकी पहचान की पुष्टि करवाई गई, और "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" व्यवस्था के तहत जिनके कार्ड थे, उन्हें वहीं राशन दिलवाया गया। ज़िला कलेक्टर को उसी दिन सूचना दी गई, जिन्होंने आदेश का समर्थन किया।

बाद में ऑडिट-दल ने पंजीकरण-रजिस्टर देखकर कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी थी। एक प्रवासी मज़दूर की पत्नी ने शिविर से लौटते समय कहा — "हम सोचते थे, परदेस में हमारा कोई नहीं; यहाँ सरकार ने हमें अपना माना।" राजेश ने आपदा-प्रबंधन की ज़िला योजना में एक नई पंक्ति जुड़वाई — "राहत शिविर में पहचान-पत्र के अभाव में किसी को भोजन से वंचित नहीं किया जाएगा।"

🔑 **इस कहानी से सीख:** मानवीय सहायता का मूल सिद्धांत निष्पक्षता है — ज़रूरत ही एकमात्र कसौटी है, पहचान, जाति, धर्म या राज्य नहीं। पर करुणा के साथ जवाबदेही भी ज़रूरी है — सरल पंजीकरण, लिखित आदेश और उच्च अधिकारियों को सूचना करुणा को पारदर्शी बनाते हैं।

भारत के प्रमुख मानवीय अभियान: मैत्री (नेपाल भूकंप, 2015), गंगा (यूक्रेन, 2022), कावेरी (सूडान, 2023), दोस्त (तुर्की-सीरिया भूकंप, 2023) और वैक्सीन मैत्री (कोविड काल) — ये भारत की "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना के व्यावहारिक रूप हैं।

5. शासन में जवाबदेही (Accountability in Governance)

☀ सामान्य सिद्धांत

जवाबदेही का अर्थ महज़ 'दोष मढ़ना' (Blame) नहीं, बल्कि 'सीखना और सुधार करना' (Learning and Improving) है — प्रशासनिक सुधार से जुड़े अधिकांश आयोगों (जैसे भारत का द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो 2005 में वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में बना, और ब्रिटेन की नोलन समिति, जो 1994 में सार्वजनिक जीवन के आचरण-मानक तय करने के लिए बनी) का यही मूल भाव रहा है।

🔍 आसान परिभाषा: जवाबदेही का सूत्र (Accountability Formula)

📌 **परिभाषा:** जवाबदेही = पारदर्शिता (Transparency) + उत्तरदेयता (Answerability) + प्रवर्तनीयता (Enforceability)।

💡 **आसान भाषा में:** जैसे एक दुकानदार ग्राहक को पक्का बिल देता है (पारदर्शिता), पूछे जाने पर सामान की गुणवत्ता का जवाब देता है (उत्तरदेयता), और ख़राब सामान वापस लेने को बाध्य होता है (प्रवर्तनीयता) — ठीक वैसे ही एक प्रशासक को अपने निर्णयों के लिए तीनों स्तरों पर उत्तरदायी होना पड़ता है। 🏠 **उदाहरण:** सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) 2005 पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, क्योंकि कोई भी नागरिक सरकारी फ़ाइलों की जानकारी माँग सकता है; संसदीय प्रश्नकाल व मीडिया उत्तरदेयता तय करते हैं, क्योंकि वहाँ मंत्रियों और अधिकारियों को सवालों के जवाब देने पड़ते हैं; तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और लोकपाल जैसी संस्थाएँ प्रवर्तनीयता (दंड/कार्रवाई) सुनिश्चित करती हैं।

जवाबदेही का अर्थ: जवाबदेही का अर्थ है — अधिकारियों का अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होना; यानी उन्हें सौंपी गई विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग का संतोषजनक हिसाब देने का दायित्व, जिसमें विफल रहने पर कोई दंड हो सकता है। यह सुनिश्चित करती है कि जब कर्तव्य और

प्रतिबद्धताएँ पूरी न हों, तो **निवारण** मिले। किसी कार्यक्रम में जवाबदेही और पारदर्शिता की मज़बूती उसकी दक्षता और प्रभावशीलता से, और अंततः लाभार्थियों तक पहुँचे लाभ की मात्रा और गुणवत्ता से मापी जाती है।

ज़िम्मेदारी बनाम जवाबदेही: ज़िम्मेदारी (Responsibility) लोक सेवक की जनता के प्रति उत्तरदायी भावना है; जबकि **जवाबदेही (Accountability)** वह विशिष्ट पद्धति और प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोक सेवक की ज़िम्मेदारी को लागू किया जाता है। ज़िम्मेदारी भीतर से आती है, जवाबदेही बाहर से तय होती है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के मन में मरीज़ को ठीक करने की जो कर्तव्य-भावना है, वह उसकी ज़िम्मेदारी है; पर अस्पताल के ऑडिट, शिकायत-जाँच या मेडिकल परिषद के सामने उसे अपने इलाज का जो हिसाब देना पड़ता है, वह उसकी जवाबदेही है। **नैतिकता और जवाबदेही का संबंध:** नैतिकता का स्तर जितना ऊँचा होगा, बाहरी नियंत्रण के मज़बूत साधनों की ज़रूरत उतनी कम होगी; और नैतिकता जितनी कम, बाहरी जवाबदेही के उतने ही शक्तिशाली साधन चाहिए।

5.1 जवाबदेही क्यों ज़रूरी है?

जवाबदेही के लाभ	जवाबदेही के ऐतिहासिक उदाहरण
जनता का विश्वास व आत्मविश्वास बढ़ता है।	लाल बहादुर शास्त्री — रेलमंत्री रहते हुए 1956 के अरियालूर रेल दुर्घटना (23 नवंबर 1956) के बाद नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दिया (इससे पहले महबूबनगर दुर्घटना, सितंबर 1956, पर उनका इस्तीफ़ा नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था)।
प्रदर्शन (Performance) में सुधार होता है।	सतीश धवन — SLV-3 प्रक्षेपण (1979) की विफलता पर स्वयं सार्वजनिक रूप से ज़िम्मेदारी ली, जबकि अगले वर्ष (1980) की सफलता का श्रेय डॉ. कलाम को दिया।
निर्णय में स्वामित्व (Ownership) आता है — जो स्वयं तय करता है, वह ज़िम्मेदार भी होता है।	ब्रिटेन की नोलन समिति (Nolan Committee, स्थापना अक्टूबर 1994) ने सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत (निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व) प्रतिपादित किए, जिनमें जवाबदेही एक मूल स्तंभ है।
उपचारात्मक अवसर (Remedial Measure) मिलता है — गलती सुधारने का मौका।	IPS मृदुल कच्छावा — धौलपुर में डकैत गिरोहों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर 'परिणाम-जवाबदेही' (Result Accountability) का उदाहरण प्रस्तुत किया।

5.2 प्रशासक किसके प्रति जवाबदेह है?

जवाबदेही का प्रकार	उपकरण व उदाहरण
1. संविधान के प्रति	संवैधानिक प्रावधानों का पालन; मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A)।
2. संसदीय क़ानूनों के प्रति	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, RTI अधिनियम 2005, व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 — नागरिक ही लोक-सेवा का 'उपभोक्ता' है।
3. संस्थाओं के प्रति	लोकपाल व लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI, CVC, CAG, निर्वाचन आयोग।
4. स्वयं के प्रति (आंतरिक)	सिटिज़न चार्टर, आंतरिक अंकेक्षण (Internal Audit), वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR)।
5. तकनीक के माध्यम से	राजस्थान संपर्क पोर्टल, जन सूचना पोर्टल (राजस्थान), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), CCTV, बायोमेट्रिक उपस्थिति।
6. नागरिकों के प्रति	CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली), सामाजिक अंकेक्षण (मनरेगा), 360-डिग्री मूल्यांकन।

ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज जवाबदेही

ऊर्ध्वाधर (Vertical)	बनाम	क्षैतिज (Horizontal)
नागरिक / मतदाता	किसके प्रति	राज्य की दूसरी संस्थाएँ
जनता से सरकार की ओर	दिशा	राज्य के अंगों के बीच
चुनाव, जन-आंदोलन, नागरिक अधिकार-पत्र, जन-प्रतिक्रिया	साधन	न्यायिक समीक्षा, संसदीय निगरानी, CAG, लोकपाल
अधूरे वादों पर मतदाता का निर्णय	उदाहरण	CAG द्वारा सरकारी खर्च की जाँच

चित्र 8.8: ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज जवाबदेही

क्षैतिज जवाबदेही की नींव — नियंत्रण और संतुलन: अमेरिकी संविधान के प्रमुख निर्माता **जेम्स मैडिसन** ने सत्ता के केंद्रीकरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन पर बल दिया — "महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा से संतुलित करो।" इसी तरह **जे.एस. मिल** ने निरंतर सार्वजनिक संवाद और आलोचना (ऊर्ध्वाधर जवाबदेही) को सुशासन के लिए अनिवार्य माना, जो अधिकारियों के नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करती है।

5.4 जवाबदेही के पाँच आयाम और विश्व बैंक की दृष्टि

जवाबदेही के मूल में तीन मूल्य हैं — **लोकतंत्र, दक्षता और नैतिकता**। विद्वानों ने जवाबदेही के कम से कम पाँच आयाम बताए हैं: **(1) वैधानिक** — अधिकारी का हर काम कानून के दायरे में हो, यानी विधि का शासन; **(2) वित्तीय** — जनता के पैसे का सही, मितव्ययी और ईमानदार उपयोग तथा उसके हर रुपये का हिसाब; **(3) नीति और प्रदर्शन** — लक्ष्य, वादे और अपेक्षाएँ पूरी करना; **(4) लोकतांत्रिक** — विधायिका और नागरिकों को सूचित करना और उनसे परामर्श; **(5) नैतिक** — आचार संहिता या सामान्य नैतिक मानकों के अनुरूप आचरण। ये आयाम रोज़मर्रा के प्रशासन में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहते हैं।

जवाबदेही के पाँच आयाम

जवाबदेही				
वैधानिक विधि का शासन	वित्तीय सार्वजनिक धन	प्रदर्शन लक्ष्य और वादे	लोकतांत्रिक विधायिका, नागरिक	नैतिक आचार संहिता

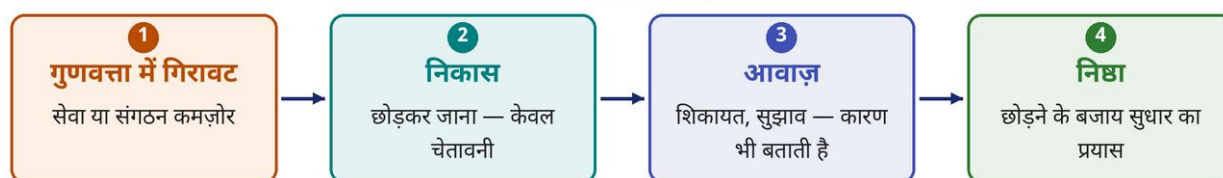
चित्र 8.9: जवाबदेही के पाँच आयाम

विश्व बैंक के अनुसार जवाबदेही के दो रूप: सूक्ष्म जवाबदेही (Micro Accountability) — सेवाएँ जनता की ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी हों; इसके लिए "निकास" (असंतुष्ट होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प, जिससे एजेंसी की आय और कर्मचारियों की सुरक्षा पर असर पड़े) और "आवाज़" (जनता की भागीदारी और शिकायत, जो सेवा की गुणवत्ता सुधारे) — दोनों को सेवा-परियोजनाओं के डिज़ाइन में ही शामिल किया जाए। **वृहद जवाबदेही (Macro Accountability)** — इसके दो आयाम हैं: **वित्तीय जवाबदेही** (सुचारु सरकारी लेखा-प्रणाली, खर्च पर नियंत्रण, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली बाहरी लेखा-परीक्षा, और ऑडिट के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई) तथा **आर्थिक प्रदर्शन की जवाबदेही** (सार्वजनिक निवेश में संसाधन-उपयोग की समीक्षा और सरकार की स्व-मूल्यांकन क्षमता)।

5.5 निकास, आवाज़ और निष्ठा का सिद्धांत (हर्शमैन)

अर्थशास्त्री **अल्बर्ट ओ. हर्शमैन** (1970) के अनुसार जब किसी संगठन (व्यवसाय, राष्ट्र या कोई भी समूह) की गुणवत्ता गिरती है, तो उसके सदस्यों के पास दो विकल्प होते हैं — **निकास (Exit)** — संबंध तोड़कर चले जाना; या **आवाज़ (Voice)** — शिकायत, सुझाव या विरोध के माध्यम से सुधार का प्रयास। जैसे बढ़ते दमन पर नागरिक या तो देश छोड़ते हैं या विरोध करते हैं; कर्मचारी या तो नौकरी छोड़ते हैं या अपनी चिंता उठाते हैं। "आवाज़" अधिक सूचनाप्रद है, क्योंकि वह गिरावट के कारण भी बताती है; "निकास" केवल चेतावनी है। असहमति को दबाने से लोग "निकास" को मजबूर होते हैं; और जहाँ **निष्ठा (Loyalty)** मज़बूत हो, वहाँ लोग छोड़ने के बजाय आवाज़ उठाना पसंद करते हैं। **प्रशासनिक अर्थ:** एक अच्छी व्यवस्था नागरिकों की "आवाज़" — शिकायत-निवारण, जनसुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण — को इतना प्रभावी बनाती है कि उन्हें व्यवस्था से "निकास" (अविश्वास, पलायन) की ज़रूरत ही न पड़े।

निकास, आवाज़ और निष्ठा



चित्र 8.10: निकास, आवाज़ और निष्ठा

5.6 शासन, सुशासन और नैतिक शासन

सरकार संप्रभु शक्ति के प्रयोग की मशीनरी और संस्थागत व्यवस्था है, जबकि **शासन (Governance)** समाज के हित में अधिकारपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसका परिणाम है — सरकार "शासन करने" से जुड़ी है, शासन "सेवा करने" से। सुशासन की जड़ें अरस्तू तक जाती हैं — **"राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया, पर अच्छे जीवन के लिए बना रहा।"** लॉक के शब्दों में सरकार तभी तक शासन करे, "जब तक वह जनता के हितों और उनके भरोसे की रक्षा कर सके।" इसी से लोकतंत्र, सहमति से शासन और सुशासन की अवधारणाएँ निकलीं।

आयाम	शासन	सुशासन	नैतिक शासन
अर्थ	हितधारकों के साथ निर्णय और क्रियान्वयन की प्रक्रिया	गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही वाला शासन	स्थापित नैतिक सिद्धांतों पर आधारित शासन
मुख्य विशेषता	निर्णय-प्रक्रिया	पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, समावेश	नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का पालन
केंद्र	नियमों और क़ानूनों का क्रियान्वयन	प्रभावी और कुशल परिणाम	अच्छे इरादे और साधन

नैतिक शासन = जवाबदेही + पारदर्शिता + निष्पक्षता + जन-विश्वास + सेवा-दक्षता। यानी नैतिक शासन तभी बनता है, जब ये पाँचों गुण एक साथ मौजूद हों — इनमें से कोई एक भी कमज़ोर हो, तो शासन पर जनता का भरोसा डगमगा जाता है। नैतिक शासन की माँग है कि लोक सेवक दूसरों की सेवा के सिद्धांत का पालन करें, नैतिक आचरण के ऊँचे मानक रखें और अपने काम को **"व्रत" (Vocation)** — सबके कल्याण को समर्पित, उद्देश्य-पूर्ण जीवन — मानें। **जवाबदेही नैतिकता का व्यावहारिक प्रवर्तन-तंत्र है** — नैतिक सिद्धांत नैतिक दिशा-सूचक हैं, पर जवाबदेही के बिना वे केवल आकांक्षाएँ रह जाते हैं। जवाबदेही नैतिक सिद्धांतों को लागू करती है, पारदर्शिता बढ़ाती है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है, जन-विश्वास और वैधता बनाती है, और सेवा-वितरण सुधारती है।

सुशासन के छह मापदंड (विश्व बैंक)	नैतिक शासन के लिए महत्व
आवाज़ और जवाबदेही	नागरिक भागीदारी, स्वतंत्र मीडिया
राजनीतिक स्थिरता, हिंसा का अभाव	शांतिपूर्ण शासन-परिवर्तन
सरकारी प्रभावशीलता	सेवाओं की गुणवत्ता
नियामक गुणवत्ता	नियम संतुलित हों — नागरिकों व व्यापार पर अनावश्यक बोझ न डालें
विधि का शासन	अपराध का दंड, अनुबंधों का पालन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों को अदालत में चुनौती की क्षमता
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण	परमिट-लाइसेंस में रिश्वत, न्यायपालिका और राजनीति में भ्रष्टाचार का अभाव

5.7 शासन में नैतिक मूल्यों को मज़बूत करना — OECD के 12 सिद्धांत

लोक सेवा में मूल्य कई रास्तों से विकसित होते हैं — **नेतृत्व, कार्य-वातावरण, व्यावहारिक आचार संहिताएँ और मूल्य-वक्तव्य, प्रशिक्षण जैसे पेशेवर समाजीकरण, जोखिम-समीक्षा और नियंत्रण।** यानी अच्छे नेतृत्व का उदाहरण, दफ़्तर का ईमानदार माहौल, स्पष्ट आचार संहिता, प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर मूल्यों का सीखना और जोखिम वाले कामों की नियमित समीक्षा — ये सब मिलकर कर्मचारियों में नैतिक मूल्य पैदा करते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के देशों ने 1998 में लोक सेवा में नैतिक आचरण सुधारने के लिए 12 सिद्धांत तैयार किए:

क्र.	सिद्धांत
1	लोक सेवा के नैतिक मानक स्पष्ट हों
2	नैतिक मानक क़ानूनी ढाँचे में परिलक्षित हों
3	लोक सेवकों को नैतिक मार्गदर्शन उपलब्ध हो
4	गलत काम उजागर करते समय लोक सेवक अपने अधिकार और दायित्व जानें
5	नैतिकता के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता लोक सेवकों के नैतिक आचरण को मज़बूत करे
6	निर्णय-प्रक्रिया पारदर्शी और जाँच के लिए खुली हो
7	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संपर्क के स्पष्ट दिशानिर्देश हों

क्र.	सिद्धांत
8	प्रबंधक नैतिक आचरण का उदाहरण बनें और उसे बढ़ावा दें
9	प्रबंधन की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और व्यवहार नैतिक आचरण को बढ़ावा दें
10	सेवा-शर्तें और मानव-संसाधन प्रबंधन नैतिक आचरण को बढ़ावा दें
11	लोक सेवा में पर्याप्त जवाबदेही-तंत्र हों
12	कदाचार से निपटने की उचित प्रक्रियाएँ और दंड हों

जवाबदेही के दो प्रसिद्ध उदाहरण: लाल बहादुर शास्त्री का रेल मंत्री पद से इस्तीफा (1956) और सतीश धवन द्वारा SLV-3 की विफलता (1979) की ज़िम्मेदारी लेना — दोनों जवाबदेही के सूत्र (पारदर्शिता + उत्तरदेयता + प्रवर्तनीयता) के जीवंत उदाहरण हैं।

📖 कहानी: "सड़क जो छह महीने में उखड़ गई" — जवाबदेही का सूत्र व्यवहार में

झुंझुनू ज़िले में एक ग्रामीण सड़क, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी, पहली ही बरसात में जगह-जगह उखड़ गई। गाँव वालों ने सोशल मीडिया पर टूटी सड़क के वीडियो डाले, और मामला ज़िला स्तर तक पहुँचा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता **विनोद** (काल्पनिक नाम) के सामने दो रास्ते थे — दोष बारिश और "असाधारण मौसम" पर डाल देना, या सच का सामना करना।

विनोद ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने स्वयं गाँव जाकर ग्रामीणों के सामने स्वीकार किया — "सड़क की गुणवत्ता में कमी हुई है, और निगरानी की ज़िम्मेदारी मेरे विभाग की थी।" फिर उन्होंने **जवाबदेही के सूत्र** के तीनों हिस्से लागू किए। **पारदर्शिता** — सड़क की स्वीकृत लागत, विनिर्देश, ठेकेदार का नाम और गुणवत्ता-जाँच की रिपोर्टें पंचायत भवन पर लगाई गईं। **उत्तरदेयता** — ग्राम सभा में खुली सुनवाई हुई, जहाँ ग्रामीणों ने सवाल पूछे और विभाग ने जवाब दिए; स्वतंत्र प्रयोगशाला से सड़क के नमूनों की जाँच करवाई गई।

प्रवर्तनीयता — जाँच में सामग्री की गुणवत्ता घटिया निकली। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से अपने खर्च पर पूरी सड़क दोबारा बनवाई गई, उसकी ज़मानत राशि ज़ब्त हुई और उसे एक वर्ष के लिए काली सूची में डाला गया; निगरानी में लापरवाही बरतने वाले कनिष्ठ अभियंता पर विभागीय कार्रवाई हुई। साथ ही विनोद ने एक सुधार भी किया — हर नई सड़क पर एक **क्यूआर कोड वाला बोर्ड** लगाया गया, जिसे स्कैन करके कोई भी नागरिक सड़क का विवरण देख सकता था और शिकायत दर्ज कर सकता था, और ग्राम सभा की एक निगरानी-समिति को निर्माण के दौरान निरीक्षण का अधिकार दिया गया।

नई सड़क अगले तीन मानसून झेल गई। ज़िले में नागरिक-शिकायतें घटीं और निर्माण की गुणवत्ता की रैंकिंग सुधरी। विनोद ने एक प्रशिक्षण में कहा — "जवाबदेही का अर्थ किसी पर दोष डालना नहीं, बल्कि सीखना और सुधार करना है। जिस दिन हमने ग़लती स्वीकारी, उसी दिन से लोगों ने हम पर भरोसा करना शुरू किया।"

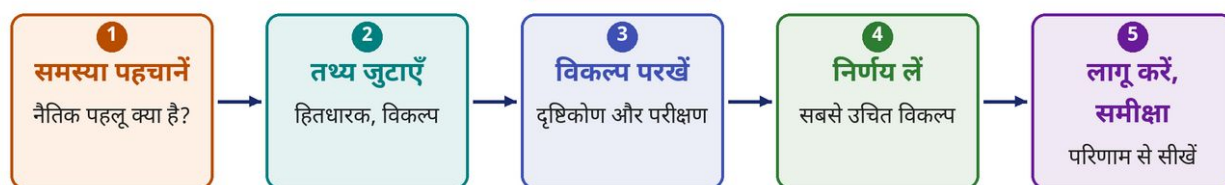
🔑 **इस कहानी से सीख:** जवाबदेही = पारदर्शिता + उत्तरदेयता + प्रवर्तनीयता। ग़लती स्वीकारना कमज़ोरी नहीं, बल्कि भरोसे की शुरुआत है। नागरिकों की "आवाज़" (सोशल मीडिया, ग्राम सभा, क्यूआर कोड) को व्यवस्था में जगह देना ही सूक्ष्म जवाबदेही का सबसे प्रभावी रूप है।

6. नैतिक निर्णय की 5-चरण प्रक्रिया एवं 10 परीक्षण

6.1 नैतिक निर्णय के 5 चरण (5 Steps)

चरण	क्या करें?	उदाहरण
चरण 1: नैतिक समस्या पहचानें	समस्या का नैतिक पहलू क्या है? किसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? कौन-सा कर्तव्य प्रभावित है?	PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का राशन नहीं मिल रहा — यह भोजन के अधिकार (Right to Food) का उल्लंघन है।
चरण 2: तथ्य जुटाएँ (कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों)	प्राथमिक हितधारक (Primary) व द्वितीयक हितधारक (Secondary) कौन हैं?	भूखा परिवार = प्राथमिक हितधारक; राशन-दुकान की बायोमेट्रिक मशीन में अँगूठा न मिलना = समस्या का तकनीकी कारण।
चरण 3: दाँव पर लगे मूल्य पहचानें	कौन-कौन से नैतिक मूल्य ख़तरे में हैं? करुणा, निष्पक्षता, जवाबदेही में से कौन प्रभावित?	करुणा बनाम नियम-पालन (Compassion vs Rule-following) — दोनों मूल्य दाँव पर।
चरण 4: विकल्पों की खोज करें	ऐसे विकल्प खोजें जो न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें; व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचें।	नियम में स्पष्ट प्रावधान न होने पर भी विवेकाधिकार (Discretion) से भोजन उपलब्ध कराने का विकल्प।
चरण 5: परिणामों का विश्लेषण करें	अल्पकालिक व दीर्घकालिक — दोनों परिणामों का आकलन करें; नीचे दिए 10 परीक्षण लगाएँ।	क्या यह निर्णय न्यायालय में टिकेगा? क्या अख़बार में छपने पर शर्मिंदगी नहीं होगी?

नैतिक निर्णय के पाँच चरण



चित्र 8.11: नैतिक निर्णय के पाँच चरण

6.2 निर्णय परखने के 10 परीक्षण (10 Tests)

परीक्षण (Test)	सरल प्रश्न	मतलब क्या है?
1. अधिकार-दृष्टिकोण (Rights Test)	क्या यह निर्णय सभी हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करता है?	क्या कोई मौलिक अधिकार तो नहीं टूट रहा?
2. न्याय-दृष्टिकोण (Justice Test)	क्या यह सभी के साथ समान व न्यायपूर्ण है? कहीं भेदभाव तो नहीं?	अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समान संरक्षण।
3. उपयोगितावादी परीक्षण (Utilitarian Test)	क्या यह अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ देगा?	बेन्थम — 'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख' (Greatest Good for Greatest Number)।
4. सामान्य भलाई परीक्षण (Common Good Test)	क्या यह पूरे समुदाय की सेवा करता है, या केवल कुछ लोगों की?	वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना।
5. सद्गुण परीक्षण (Virtue Test)	क्या इस निर्णय से मैं एक बेहतर इंसान बनूँगा?	अरस्तू — चरित्र-निर्माण (Character Development)।
6. देखभाल-नैतिकता परीक्षण (Care Ethics Test)	क्या यह सभी हितधारकों के रिश्तों व भावनाओं का ध्यान रखता है?	देखभाल-नैतिकता (Care Ethics) — अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरल गिलिगन (Carol Gilligan)।
7. हानि परीक्षण (Harm Test)	क्या इससे लोगों या पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान होगा?	न्यूनतम हानि सिद्धांत (Minimum Harm Principle)।
8. उलटाव परीक्षण (Reversibility Test)	यदि मैं उस प्रभावित व्यक्ति की जगह होता, तो कैसा महसूस करता?	जॉन रॉल्स — 'अज्ञानता का आवरण' (Veil of Ignorance)।
9. प्रचार परीक्षण (Publicity Test)	यदि यह निर्णय कल अखबार में छपे, तो क्या मुझे शर्मिंदगी होगी?	"प्रशासन न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखे भी।"
10. बचाव परीक्षण (Defensibility Test)	क्या यह निर्णय किसी क़ानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? क्या यह न्यायालय में टिकेगा?	विधि का शासन (Rule of Law) — संवैधानिकता।

New India Education by Omkar Sir

निर्णय परखने के प्रमुख परीक्षण

मेरा निर्णय

प्रचार परीक्षण क्या यह अखबार में छपने लायक है?	उलट परीक्षण अगर मैं प्रभावित होता, तो?	हानि परीक्षण कैसे कितनी हानि?
अधिकार परीक्षण क्या सबके अधिकार सुरक्षित हैं?	न्याय परीक्षण क्या सबसे समान व्यवहार?	सद्गुण परीक्षण क्या यह मेरे चरित्र के अनुरूप है?

चित्र 8.12: निर्णय परखने के प्रमुख परीक्षण

किसी भी नैतिक निर्णय में 5-चरण प्रक्रिया ढाँचे का काम करती है, और 10 परीक्षणों में से **प्रचार परीक्षण (Publicity)**, **उलटाव परीक्षण (Reversibility)** और **हानि परीक्षण (Harm)** सबसे व्यावहारिक हैं — इन्हें हर कठिन निर्णय पर लागू करना चाहिए।

7. नैतिक निर्णय में योगदान करने वाले कारक

एक नैतिक निर्णय तीन स्तरों पर कारकों से प्रभावित होता है — व्यक्तिगत, संगठनात्मक व सामाजिक। तीनों स्तरों को समझना किसी भी निर्णय को बहु-आयामी (multi-dimensional) दृष्टि से देखने में सहायक है।

7.1 व्यक्तिगत स्तर (Individual Level)

कारक	व्याख्या	उदाहरण
दृष्टिकोण (Attitude)	नीति-निर्माता का दृष्टिकोण नीति की दिशा तय करता है।	महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण → बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बेहतर लैंगिक-नीति।
ज्ञान (Knowledge)	लोकसंग्रह व व्यापक कल्याण का ज्ञान स्वकेंद्रित निर्णय से रोकता है।	नोबेल पुरस्कार-विजेता कैलाश सत्यार्थी — बाल-श्रम के विरुद्ध ज्ञान-आधारित संघर्ष।
व्यक्तिगत मूल्य (Values)	अहिंसा, सत्य जैसे मूल्य कार्य-दिशा तय करते हैं।	गांधीजी — चौरी-चौरा कांड (1922) के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया।
क्रान्ती जागरूकता	क्रान्ती का ज्ञान बेहतर निर्णय व अधिकार-संरक्षण सुनिश्चित करता है।	घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता — विधिक साक्षरता कार्यक्रम।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)	संवेदनशील स्थिति में संयम व संवाद-कौशल।	पुलिस अधिकारी — बलप्रयोग की बजाय बातचीत से स्थिति नियंत्रण (De-escalation)।
जवाबदेही	व्यक्तिगत उत्तरदायित्व-बोध निर्णयों को गंभीर बनाता है।	थाना प्रभारी — क्षेत्र में अपराध होने पर स्वयं जवाबदेह मानकर नियमित निगरानी।
हितों का टकराव (Conflict of Interest)	व्यक्तिगत हित निर्णय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।	क्रिकेट चयन-समिति का सदस्य, जिसका पुत्र स्वयं चयन-परीक्षण में हो — स्वयं को अलग करना (Recusal)।
अंतरात्मा (Conscience)	आंतरिक नैतिक कम्पास निर्णय की अंतिम कसौटी है।	गांधीजी का मांस न खाने का व्यक्तिगत संकल्प — आंतरिक नैतिक प्रतिबद्धता का उदाहरण।

नैतिक निर्णय को प्रभावित करने वाले तीन स्तर



चित्र 8.13: नैतिक निर्णय को प्रभावित करने वाले तीन स्तर

7.2 भावनात्मक बुद्धिमत्ता — नैतिक निर्णय की भीतरी शक्ति

व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला गुण है **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)** — अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और सकारात्मक परिणामों के लिए उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता (डैनियल गोलमैन का मॉडल)। इसके चार घटक नैतिक निर्णय में इस तरह मदद करते हैं: **(1) आत्म-जागरूकता** — निर्णय को प्रभावित कर सकने वाले अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना; **(2) आत्म-नियंत्रण** — क्रोध, भय या लोभ से प्रेरित आवेगपूर्ण निर्णयों से बचना; **(3) समानुभूति** — निर्णय का सभी हितधारकों, विशेषकर कमज़ोर वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव समझना; **(4) सामाजिक कौशल** — नैतिक निर्णय को प्रभावी ढंग से समझाना और टकराव सुलझाना।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित हो? यह गुण जन्मजात ही नहीं होता, अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। रोज़ कुछ समय आत्म-चिंतन करें — अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहें और डायरी लिखें; सहकर्मियों और वरिष्ठों से अपने व्यवहार पर ईमानदार प्रतिक्रिया (Feedback) लें; दूसरों की बात ध्यान से सुनें और स्वयं को उनकी जगह रखकर सोचें; ध्यान, व्यायाम जैसी तनाव-प्रबंधन की तकनीकें अपनाएँ; प्रशिक्षण में भूमिका-निर्वाह (Role-play) से कठिन स्थितियों का अभ्यास करें; और किसी अनुभवी वरिष्ठ से मार्गदर्शन (Mentorship) लें। **उदाहरण:** मान लीजिए किसी दबाव भरी परियोजना में आपके एक होनहार कनिष्ठ अधिकारी से बड़ी गलती हो जाती है, जिससे देरी होती है; वह तनाव में है और दंड से डरा हुआ है। आपका पहला आवेग उसे कठोरता से फटकारने का होता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान अधिकारी पहले अपने क्रोध को नियंत्रित करेगा, अकेले में शांति से बात करेगा, गलती के कारण समझेगा, सुधार की योजना साथ बनाएगा और टीम को सीख देगा — अनुशासन भी बना रहेगा और अधिकारी का

मनोबल भी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोक सेवकों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जो सैद्धांतिक भी हों, व्यावहारिक भी, संवेदनशील भी और प्रभावी भी।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

आत्म-जागरूकता

अपने पूर्वाग्रह पहचानना

आत्म-नियंत्रण

आवेगपूर्ण निर्णय से बचना

समानुभूति

कमज़ोर पर असर समझना

सामाजिक कौशल

संवाद, टकराव-समाधान

चित्र 8.14: भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय

7.3 संगठनात्मक स्तर (Organizational Level)

कारक	उदाहरण
अंकेक्षण व पारदर्शिता (Audit & Transparency)	मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण, सरकारी कार्यालयों में RTI का प्रभाव — आज कोई लोकसेवक जब फ़ाइल पर टिप्पणी लिखता है, तो वह जानता है कि यह RTI के तहत जनता के सामने आ सकती है, इसलिए वह सोच-समझकर और नियम के अनुसार लिखता है।
नेतृत्व/निदेशक मंडल (Leadership)	विविधतापूर्ण बोर्ड — TATA, Wipro जैसी कंपनियाँ; डॉ. समित शर्मा (IAS) — चित्तौड़गढ़ में जेनेरिक दवा सुधार मॉडल, बाद में 2011 से 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' के रूप में पूरे राजस्थान में विस्तारित।
कर्मचारी सहभागिता (Employee Participation)	हीरो साइकल — ओ.पी. मुंजाल का मॉडल; OYO — वर्ष 2020 के संकट में अवकाश (फ़र्लो) पर भेजे गए कर्मचारियों को ESOP (शेयर स्वामित्व) देकर हिस्सेदार बनाया।
प्रक्रिया-सत्यनिष्ठा (Process Integrity)	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग चयन → LBSNAA (लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी)/HCM RIPA (राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर) में प्रशिक्षण → क्षेत्रीय नियुक्ति — यह संपूर्ण प्रक्रिया बेहतर निर्णय-क्षमता सुनिश्चित करती है।
संगठनात्मक मूल्य (Organizational Values)	सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, पारदर्शिता, जवाबदेही — ये मूल मूल्य (Core Values) संगठन की दिशा तय करते हैं।
विधिक अंकुश (Legal Sanctions)	भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964।
केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण	अति-केंद्रीकरण से थोपे गए निर्णय बनते हैं, जबकि अति-विकेंद्रीकरण से अकुशलता आती है — संतुलन आवश्यक।
प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programs)	मिशन कर्मयोगी — सिविल सेवकों की क्षमता-निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।

7.4 सामाजिक स्तर (Social Level)

कारक	उदाहरण
सामाजिक मूल्य	वसुधैव कुटुम्बकम्, सहिष्णुता, करुणा।
आधुनिक अवधारणाएँ	नारीवादी नैतिकता (Feminist Ethics) — BCCI (27 अक्टूबर 2022) ने महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर्स के समान मैच-फ़ीस देने की घोषणा की; #MeToo, Black Lives Matter जैसे वैश्विक आंदोलन।
विधिक प्रतिबंध	PCPNDT अधिनियम 1994 (गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व लिंग-चयन निषेध) — लिंग-समानता हेतु; शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009।
न्यायिक व्याख्या	उच्चतम न्यायालय — सबरीमाला निर्णय, ट्रिपल तलाक़ निर्णय।
सरकारी नीतियाँ	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (राजस्थान) — शिक्षा जारी रखने के निर्णय को प्रोत्साहन।

प्रशासनिक नैतिकता के निर्धारक — चार स्तर: (1) **व्यक्तिगत गुण** — नैतिक निर्णय-कौशल, मानसिक दृष्टिकोण, सद्गुण और पेशेवर मूल्य; (2) **संगठनात्मक संरचना** — स्पष्ट जवाबदेही, सहयोगी व्यवस्थाएँ, असहमति के माध्यम और भागीदारी की प्रक्रियाएँ; (3) **संगठनात्मक संस्कृति** — प्रतीक, विश्वास, मूल्य और मान्यताएँ; नेतृत्व इस संस्कृति के निर्माण, संरक्षण और बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण है — नैतिक आचरण तब बढ़ता है, जब संगठन में व्यक्तिगत मानकों और प्रशिक्षण पर बल हो, पर्यवेक्षक सत्य पर ज़ोर दें और कर्मचारी नियमित रूप से मिलकर नैतिक समस्याओं पर चर्चा करें; (4) **सामाजिक अपेक्षाएँ** — जन-भागीदारी, क़ानून और नीतियाँ।

तीन-स्तरीय ढाँचा (व्यक्तिगत-संगठनात्मक-सामाजिक) बताता है कि कोई भी नैतिक निर्णय केवल व्यक्ति का नहीं होता — संस्था और समाज भी उसे आकार देते हैं।

8. साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता (Instrumental vs Value Rationality)

8.1 तार्किकता (Rationality) क्या है?

 **आसान परिभाषा: तार्किकता (Rationality) — मैक्स वेबर (1864-1920) के अनुसार**

 **परिभाषा:** तार्किकता का अर्थ है — अंधविश्वासों की बजाय तर्क, साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। युक्तिकरण (Rationalization) की प्रक्रिया में विश्वास (Belief) का स्थान तर्क (Reason) लेता है, और अनौपचारिकता (Informality) का स्थान नियम (Rules) लेते हैं।

 **आसान भाषा में:** जैसे पुराने समय में फ़सल की बुआई शुभ-मुहूर्त देखकर की जाती थी, पर आज मौसम-पूर्वानुमान व मिट्टी-परीक्षण के वैज्ञानिक आँकड़ों पर आधारित होती है — यही 'तार्किकीकरण' की प्रक्रिया है।  **उदाहरण:** आधुनिक नौकरशाही में भर्ती योग्यता (Merit) पर आधारित है (संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा), न कि जन्म या व्यक्तिगत संबंध पर — यह तार्किकता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

8.2 तार्किकता की प्रशासनिक भूमिका

भूमिका	व्याख्या	उदाहरण
नैतिक उन्नति	एक पुराना, कम-तार्किक समाज धीरे-धीरे अधिक-तार्किक समाज में परिवर्तित होता है।	राजा राममोहन राय व गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक — सती प्रथा उन्मूलन (1829), अंधविश्वास पर तर्क की विजय।
आधुनिक नौकरशाही की नींव	वेबर के अनुसार नौकरशाही नियमों व प्रक्रियाओं पर टिकी है, न कि व्यक्तिगत विश्वासों/भावनाओं पर।	योग्यता-आधारित चयन (संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग)।
निष्पक्षता व दक्षता	पदोन्नति, स्थानांतरण, नियुक्ति — तर्कसंगत नियमों पर आधारित हों।	निष्पादन-आधारित मूल्यांकन (Performance-linked Appraisal)।
विश्वास का निर्माण	तर्कसंगत प्रशासक नागरिकों को साक्ष्य के आधार पर सहजता से समझा (Persuade) सकता है।	आँकड़ा-आधारित नीति-निर्माण (Data-driven Policy Making)।

8.3 मैक्स वेबर — सामाजिक क्रिया के चार प्रकार

मैक्स वेबर ने मनुष्य के सामाजिक कर्मों को उनके पीछे की प्रेरणा के आधार पर चार प्रकारों में बाँटा। साधनभूत और मूल्य तार्किकता इन्हीं में से पहले दो प्रकार हैं; बाक़ी दो — भावात्मक और परंपरागत — तर्क से कम और भावना या आदत से अधिक संचालित होते हैं:

क्रिया का प्रकार	अर्थ	प्रशासनिक उदाहरण
साधनभूत-तार्किक (लक्ष्य-तार्किक)	लक्ष्य तय, और उसे पाने के सबसे कुशल साधन का गणना-आधारित चुनाव	कम लागत में अधिक सड़कें बनाने की योजना
मूल्य-तार्किक	किसी मूल्य (कर्तव्य, न्याय, धर्म) में दृढ़ विश्वास से किया गया कर्म, परिणाम चाहे जो हो	नुकसान के बावजूद सच बोलना, दबाव में भी नियम का पालन
भावात्मक (Affective)	भावनाओं — क्रोध, प्रेम, सहानुभूति — से प्रेरित कर्म	किसी पीड़ित को देखकर तुरंत मदद
परंपरागत (Traditional)	आदत या परंपरा से — "हमेशा से ऐसा ही होता आया है"	बिना कारण पुरानी प्रक्रिया दोहराते रहना

वेबर — सामाजिक क्रिया के चार प्रकार

सामाजिक क्रिया

साधनभूत-तार्किक

सबसे कुशल साधन

मूल्य-तार्किक

मूल्य में दृढ़ विश्वास

भावात्मक

भावना से प्रेरित

परंपरागत

आदत, परंपरा

चित्र 8.15: वेबर — सामाजिक क्रिया के चार प्रकार

8.4 मैक्स वेबर के 2 प्रकार — विस्तृत तुलना

एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण

मैक्स वेबर के सिद्धांत की एक लोकप्रिय व्याख्या यूँ की जा सकती है — 'साधनभूत तार्किकता पिंजरा बनाती है; मूल्य तार्किकता उसमें आत्मा जीवित रखती है' — ध्यान रहे यह वेबर का शब्दशः कथन नहीं, बल्कि उनके सिद्धांत की एक सरल व्याख्या (Interpretation) मात्र है।

आयाम	साधनभूत तार्किकता (Zweckrationalität)	मूल्य तार्किकता (Wertrationalität)
जर्मन नाम	Zweckrationalität (Zweck = लक्ष्य/उद्देश्य)	Wertrationalität (Wert = मूल्य)
मार्गदर्शक तत्व	दक्षता, लागत-लाभ गणना, लक्ष्य-प्राप्ति	न्याय, समता, मानवता, सत्यनिष्ठा
मूल प्रश्न	"क्या यह तरीका सबसे अच्छा परिणाम देगा?"	"क्या यह कार्य नैतिक रूप से सही है?"
तर्क का स्वरूप (Logic)	परिणाम-केंद्रित तर्क (Logic of Consequence)	औचित्य-केंद्रित तर्क (Logic of Appropriateness)
स्वभाव (Nature)	वस्तुपरक/अनुभवजन्य (Positive/Empirical) — तथ्यों पर आधारित	आदर्शात्मक (Normative) — आदर्शों पर आधारित
नैतिक आधार	परिणामवाद, उपयोगितावाद (बेन्थम, मिल, कौटिल्य)	कर्तव्यवाद, कांट, जॉन रॉल्स, भगवद्गीता
मनुष्य की स्थिति	मनुष्य = आर्थिक संसाधन (साधन)	मनुष्य = गरिमा-युक्त नैतिक कर्ता (साध्य)
कैसे रोकती है?	लालच/ताशाही (Red Tapism) को रोकती है — काम को तेज़ और परिणाम-केंद्रित बनाकर	सत्तावाद (Authoritarianism) को रोकती है — शक्ति को नैतिक सीमाओं में बाँधकर
समस्या/खतरा	लोहे का पिंजरा (Iron Cage) — बिना नैतिकता के दक्षता = अमानवीय शासन	अव्यावहारिक आदर्शवाद — बिना दक्षता के नैतिकता = नैतिक पक्षाघात, नीतिगत विलंब
उदाहरण	JAM त्रिमूर्ति (जन धन+आधार+मोबाइल); आपातकाल में जबरन नसबंदी (जनसंख्या-नियंत्रण लक्ष्य)	RTI अधिनियम 2005 (पारदर्शिता ही मूल्य है), मनरेगा (श्रम की गरिमा ही मूल्य है)
संबंधित विचारक	जेरेमी बेन्थम, जॉन स्टुअर्ट मिल, कौटिल्य	अरस्तू, कांट, जॉन रॉल्स, भगवद्गीता

साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता

साधनभूत	बनाम	मूल्य
कैसे सबसे कुशलता से?	प्रश्न	क्या यह सही है?
दक्षता, गणना	केंद्र	न्याय, कर्तव्य, गरिमा
लोहे का पिंजरा — अमानवीय	अति का खतरा	नैतिक पक्षाघात — अव्यावहारिक
लक्ष्य, आँकड़े, लागत-लाभ	उदाहरण	सामाजिक न्याय, मानवाधिकार

चित्र 8.16: साधनभूत बनाम मूल्य तार्किकता

लोहे का पिंजरा (Iron Cage Problem)	नैतिक पक्षाघात (Moral Paralysis)
◆ मैक्स वेबर की चेतावनी — केवल दक्षता पर बल देने से अमानवीय प्रशासन जन्म लेता है।	◆ केवल मूल्यों पर बल देने से भी व्यावहारिक कार्य ठप हो सकता है।
◆ मशीन जैसी नौकरशाही — जहाँ संवेदना (Empathy) शून्य हो जाती है।	◆ यूटोपियाई आदर्शवाद — व्यावहारिक क्रियान्वयन असंभव हो जाता है।
◆ आपातकाल में जबरन नसबंदी — लक्ष्य पूरा हुआ, पर गरिमा खो गई।	◆ बिना दक्षता के कल्याणकारी योजनाएँ — करदाता का धन व्यर्थ जाता है।
◆ 'कुशल पर अन्यायपूर्ण' (Efficient but Unjust) — यही लोहे का पिंजरा है।	◆ 'न्यायपूर्ण पर अकुशल' (Just but Inefficient) — यही नैतिक पक्षाघात है।

परिणाम-परिदृश्य — 4 संभावनाएँ

परिदृश्य	साधनभूत तार्किकता	मूल्य तार्किकता	परिणाम
आदर्श (Ideal)	उपस्थित	उपस्थित	कुशल + नैतिक शासन (Efficient + Ethical Governance)

परिदृश्य	साधनभूत तार्किकता	मूल्य तार्किकता	परिणाम
लोहे का पिंजरा (Iron Cage)	उपस्थित	अनुपस्थित	कुशल पर अन्यायपूर्ण — अमानवीयकृत
नैतिक पक्षाघात	अनुपस्थित	उपस्थित	न्यायपूर्ण पर अकुशल — यूटोपियाई
अराजकता	अनुपस्थित	अनुपस्थित	शासन की संपूर्ण विफलता

चार परिदृश्य — दोनों तार्किकताओं का मेल

दोनों उपस्थित कुशल और नैतिक शासन — आदर्श	केवल साधनभूत कुशल पर अमानवीय — लोहे का पिंजरा
केवल मूल्य नैतिक पर अप्रभावी — यूटोपिया	दोनों अनुपस्थित अक्षम और अनैतिक — कुशासन

चित्र 8.17: चार परिदृश्य — दोनों तार्किकताओं का मेल

ध्यान रहे: मैक्स वेबर (1864-1920) ने चेताया था कि आधुनिक समाज नियमों, गणना और दक्षता की ऐसी जकड़ में फँस सकता है, जिसमें मनुष्य एक बड़ी मशीन का पुर्जा भर रह जाए — इसी को उन्होंने 'लोहे का पिंजरा' कहा। लोहे का पिंजरा (Iron Cage) और नैतिक पक्षाघात (Moral Paralysis) — दोनों समस्याएँ साथ समझनी चाहिए; आदर्श प्रशासन दोनों तार्किकताओं के संतुलन से बनता है, किसी एक की अति से नहीं।

9. आगे की राह — संतुलित दृष्टिकोण (Way Forward)

☀ महात्मा गांधी

"साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान; साधन और साध्य के बीच वैसा ही अटूट संबंध है, जैसा बीज और वृक्ष के बीच।" (The means may be likened to a seed, the end to a tree; and there is just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree. — हिंद स्वराज, 1909)

- ◆ अगर प्रशासन केवल साधनभूत तार्किकता (दक्षता, लक्ष्य, आँकड़े) पर चले, तो वह 'लोहे का पिंजरा' बन जाता है — काम तेज़ी से होता है, पर लोगों के साथ अन्याय होता है, और ऐसा शासन लंबे समय तक टिक नहीं पाता (असंभारणीय), क्योंकि जनता का भरोसा टूट जाता है।
- ◆ अगर प्रशासन केवल मूल्य तार्किकता (आदर्श और सिद्धांत) पर चले और कुशल क्रियान्वयन की चिंता न करे, तो वह 'यूटोपिया' (कल्पना-लोक) बन जाता है — नीतियाँ सुनने में आदर्श लगती हैं, पर ज़मीन पर लागू नहीं हो पाती।
- ◆ गांधी (जो साधन और साध्य — दोनों की पवित्रता पर बल देते थे) और अमर्त्य सेन (जो नीति को इस बात से परखते हैं कि उससे लोगों की वास्तविक क्षमता कितनी बढ़ी) — दोनों की सीख यही है कि दक्षता और मूल्य एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर-पूरक (Complementary) हैं; एक के बिना दूसरा अधूरा है।
- ◆ इसलिए प्रशासक को चाहिए कि वह साधनभूत तार्किकता से दक्षता और मूल्य तार्किकता से नैतिकता लेकर दोनों का समन्वय करे — यही कुशल व नैतिक शासन (Efficient + Ethical Governance) है।

☀ राजस्थान का उदाहरण — भीलवाड़ा मॉडल

कोविड-19 के समय भीलवाड़ा में साधनभूत तार्किकता कठोर लॉकडाउन और ज़िले की सीमाएँ सील करने के रूप में दिखी, ताकि संक्रमण को तेज़ी और कुशलता से रोका जा सके; वहीं मूल्य तार्किकता प्रवासी मज़दूरों तक भोजन पहुँचाने और संवेदनशील पुलिसिंग (Compassionate Policing) के रूप में दिखी, ताकि सख्ती के बीच भी किसी की गरिमा न टूटे। दोनों का संतुलन ही 'भीलवाड़ा मॉडल' को शासन का एक अनुकरणीय उदाहरण बनाता है — जिसे राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक सराहना मिली।

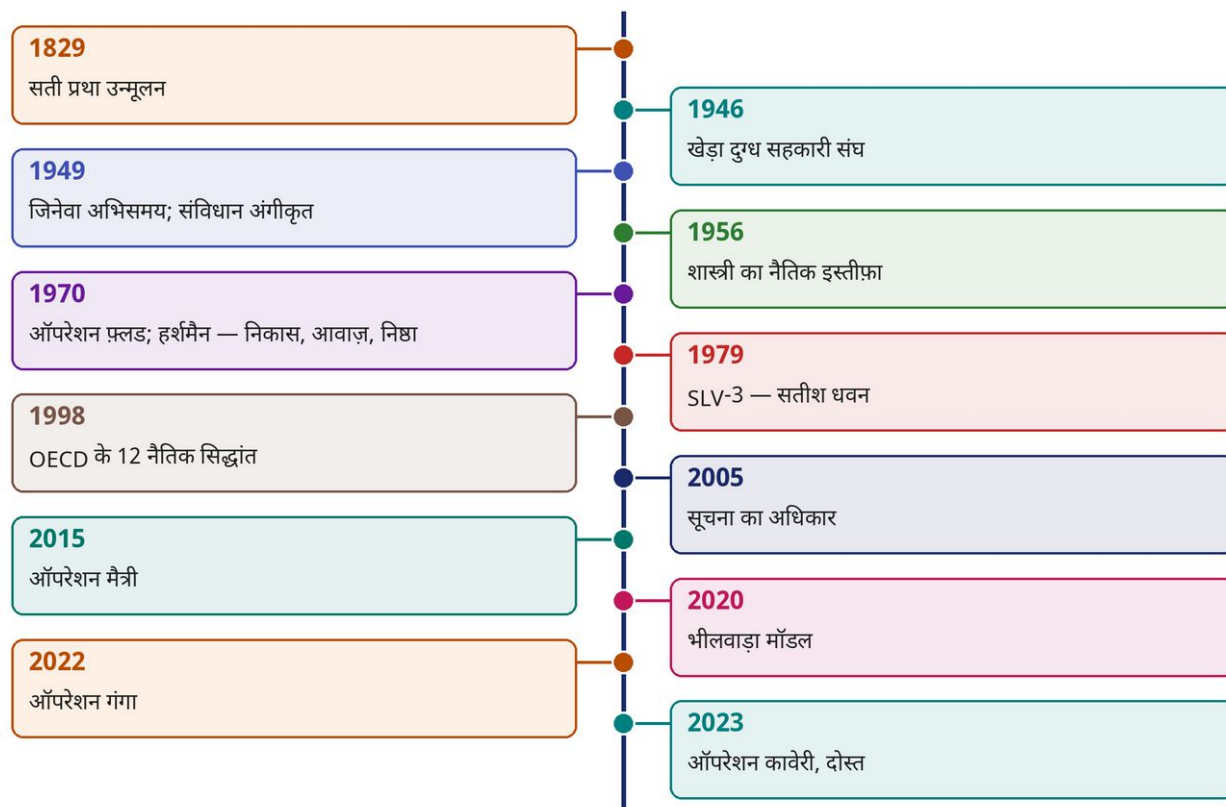
अध्याय का सार-सूत्र: सामाजिक न्याय — ROPE सूत्र (संसाधन, अवसर, विशेषाधिकार, सशक्तीकरण); मानवीय चिंताएँ — मैत्री, गंगा, कावेरी, दोस्त, वैक्सीन मैत्री; जवाबदेही — पारदर्शिता + उत्तरदेयता + प्रवर्तनीयता, शास्त्री (1956) और सतीश धवन (1979); निर्णय — 5 चरण और प्रचार, उलटाव तथा हानि परीक्षण; और तार्किकता — साधनभूत तथा मूल्य तार्किकता का संतुलन।

10. नैतिक निर्णय-निर्माण — ऐतिहासिक यात्रा

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1829	राजा राममोहन राय व गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक — सती प्रथा उन्मूलन — तार्किकीकरण व सामाजिक-सुधार का ऐतिहासिक उदाहरण।
1864-1920	मैक्स वेबर (जर्मन समाजशास्त्री) का जीवनकाल — साधनभूत व मूल्य तार्किकता (Zweckrationalität/Wertrationalität) तथा नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक।

वर्ष / संदर्भ	विषय / घटना
1949-50	भारतीय संविधान — संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 26 जनवरी 1950 से लागू; अनुच्छेद 38, 39 (नीति-निदेशक तत्व) — सामाजिक न्याय का संवैधानिक आधार।
1956	लाल बहादुर शास्त्री — अरियालूर रेल दुर्घटना (23 नवंबर) के बाद रेल मंत्री पद से नैतिक जवाबदेही स्वरूप इस्तीफा — जवाबदेही का सर्वोच्च उदाहरण।
1979	इसरो का SLV-3 प्रक्षेपण असफल — सतीश धवन ने स्वयं ज़िम्मेदारी ली।
2004	हिंद महासागर सुनामी — भारत ने श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया को राहत सहायता दी — मानवीय चिंता का उदाहरण।
2005	सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) पारित — मूल्य तार्किकता (पारदर्शिता) का प्रतिष्ठित उदाहरण।
2015	नेपाल भूकंप — 'ऑपरेशन मैत्री' — भारत की मानवीय सहायता।
2018	केरल बाढ़ — IAS कन्नन गोपीनाथन व MG राजामणिक्यम की करुणाशील प्रशासनिक भूमिका।
2020	कोविड-19 — भीलवाड़ा मॉडल (टीना डाबी व राजेंद्र भट्ट) — दोनों तार्किकताओं का संतुलन; 'वैक्सीन मैत्री' पहल — लगभग 100 देशों को वैक्सीन आपूर्ति।
2022	यूक्रेन युद्ध — 'ऑपरेशन गंगा' — लगभग 22,500 भारतीयों की सुरक्षित निकासी।
2023	सूडान से 'ऑपरेशन कावेरी' द्वारा भारतीयों की निकासी और तुर्की-सीरिया भूकंप में 'ऑपरेशन दोस्त' द्वारा राहत; भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) पारित।

नैतिक निर्णय-निर्माण — प्रमुख पड़ाव



चित्र 8.18: नैतिक निर्णय-निर्माण — प्रमुख पड़ाव

☀ अध्याय का सार — एक पंक्ति में

एक नैतिक प्रशासनिक निर्णय न तो केवल दक्षता (साधनभूत तार्किकता) पर टिक सकता है, न केवल आदर्शों (मूल्य तार्किकता) पर — बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदनशीलता व जवाबदेही की ठोस बुनियाद पर खड़े होकर, 5-चरण प्रक्रिया व 10 परीक्षणों जैसे व्यवस्थित उपकरणों की मदद से, दोनों तार्किकताओं के बीच संतुलन साधने से ही बनता है — यही भीलवाड़ा मॉडल जैसे उदाहरणों का असली सार है।

बोनस: उत्तर-लेखन अभ्यास (मॉडल प्रश्न और उत्तर)

प्रश्न 1: "नैतिक निर्णय" लेने में आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। यदि निर्णय प्रशासनिक आदेश के विरुद्ध हो तो उनमें सामंजस्य कैसे करेंगे?

उत्तर: एक नैतिक निर्णय के लिए आवश्यक तत्वों को इस अध्याय के 14 आधारों में समेटा जा सकता है — इनमें प्रमुख हैं ईमानदारी व सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, मानवाधिकार-सम्मान, जवाबदेही, स्पष्ट अंतरात्मा तथा परिणामों की चिंता। साथ ही, निर्णय की प्रक्रिया 5-चरण ढाँचे (समस्या-पहचान →

तथ्य-संकलन → मूल्य-पहचान → विकल्प-खोज → परिणाम-विश्लेषण) से गुज़रनी चाहिए, और अंत में उसे 10 परीक्षणों (विशेषकर प्रचार, उलटाव व हानि परीक्षण) पर परखा जाना चाहिए।

◆ **टकराव की स्थिति:** जब व्यक्तिगत नैतिक निर्णय प्रशासनिक आदेश से टकराए (जैसे कोई आदेश संवैधानिक मूल्यों या मानवाधिकार का उल्लंघन करता प्रतीत हो), तो सर्वप्रथम आदेश की वैधानिकता व औचित्य की समीक्षा उचित संस्थागत माध्यम से करनी चाहिए — जैसे लिखित में स्पष्टीकरण माँगना (कार्य-संचालन नियम — Rules of Business — के अंतर्गत)।

◆ **सामंजस्य के उपाय:** (1) वरिष्ठ अधिकारी से लिखित निर्देश माँगना — इससे जवाबदेही स्पष्ट होती है; (2) यदि आदेश स्पष्टतः अवैध/अनैतिक हो, तो संवैधानिक व वैधानिक प्रावधानों (जैसे सिविल सेवा आचरण नियम) के अनुरूप विनम्र असहमति दर्ज करना; (3) गांधीजी के जंतर (Talisman) का प्रयोग — यह जाँचना कि निर्णय समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए उपयोगी है या नहीं; (4) अंतिम उपाय के रूप में विवेक-आधारित इनकार (Conscientious Objection) व उचित शिकायत-तंत्र (जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग — CVC) का प्रयोग।

निष्कर्ष: नैतिक निर्णय व प्रशासनिक आदेश के बीच टकराव को पूर्णतः टाला नहीं जा सकता, पर एक जागरूक लोक सेवक संस्थागत प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यों व अपनी अंतरात्मा के संतुलित प्रयोग से इसे उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से सुलझा सकता है।

प्रश्न 2: "साधनभूत तार्किकता के बिना मूल्य तार्किकता एक यूटोपिया है, और मूल्य तार्किकता के बिना साधनभूत तार्किकता एक लोहे का पिंजरा है।" इस कथन की विवेचना करें।

उत्तर: यह कथन मैक्स वेबर की तार्किकता (Rationality) की दो श्रेणियों — साधनभूत तार्किकता (Zweckrationalität) व मूल्य तार्किकता (Wertrationalität) — के अंतर्संबंध को उजागर करता है।

◆ **'यूटोपिया' का अर्थ:** यदि प्रशासन केवल आदर्शों/मूल्यों (न्याय, समता, करुणा) पर चले, पर दक्षता व व्यावहारिक क्रियान्वयन-क्षमता का अभाव हो, तो नीतियाँ कागज़ पर तो न्यायपूर्ण दिखेंगी, पर व्यवहार में लागू नहीं हो पाएँगी — यही 'नैतिक पक्षाघात' (Moral Paralysis) की स्थिति है, जैसे बिना दक्ष क्रियान्वयन-तंत्र के कोई कल्याणकारी योजना।

◆ **'लोहे का पिंजरा' का अर्थ:** यदि प्रशासन केवल दक्षता व लक्ष्य-प्राप्ति (साधनभूत तार्किकता) पर चले, बिना नैतिक मूल्यों की परवाह किए, तो व्यवस्था तकनीकी रूप से कुशल तो होगी, पर मानवीय गरिमा-विहीन व अमानवीय बन जाएगी — जैसे आपातकाल में जबरन नसबंदी अभियान, जहाँ लक्ष्य पूरा हुआ पर गरिमा की कीमत पर।

◆ **संतुलन की आवश्यकता:** भीलवाड़ा मॉडल इस बात का प्रमाण है कि दक्षता (कठोर लॉकडाउन, सीमा-सीलिंग) व मूल्य (प्रवासियों के प्रति करुणा) — दोनों को साथ लेकर चलने पर ही आदर्श शासन (Efficient + Ethical Governance) संभव है।

निष्कर्ष: महात्मा गांधी व अमर्त्य सेन के विचार यहाँ पूरक सिद्ध होते हैं — साधन (दक्षता) व साध्य (नैतिकता), दोनों की पवित्रता व संतुलन ही स्थायी व न्यायपूर्ण शासन का आधार है।

